

प्रेषक,

एम०एच० खान,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
पौड़ी।

पेयजल अनुभाग-२

देहरादून : दिनांक १९ मई, २००८

विषय :- इण्डिया मार्क-१। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु वित्तीय वर्ष २००८-०९ में राज्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, अप्रैल, उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्र संख्या ५२५५/अप्रै०-०३/हैण्डपम्प/२००७-०८ दिनांक २९.१२.२००७ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला योजना के अन्तर्गत इण्डिया मार्क-१। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु ₹० ७७.४६ लाख के प्राक्कलनों पर टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹० ७६.२६ लाख (रुपये छिहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२. जिला योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार आहरण के पूर्व जनपदवार जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा अनुमोदित परिष्वय एवं योजनाओं के अनुरूप ही किया जायेगा। परिष्वय से अधिक धनराशि के आहरण का दायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का ही माना जायेगा।

३. प्रस्तर-१ में स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जनपद के अधिशासी अभियन्ता /नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन को तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

४. हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या ३०९३/उन्तीस/०५-२(५०पे०)/२००४ दिनांक १८ जनवरी, २००५ एवं शासनादेश संख्या १०१६/उन्तीस/०५-२-पे०/२००५, दिनांक १५ अप्रैल, २००५ द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

५. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

६. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2009 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा। कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन ऐसे स्थानों पर किया जायेगा जो क्षेत्र वास्तव में अभावग्रस्त हैं तथा इसका लाभ अधिक से अधिक जनसंख्या को प्राप्त हो सकें।
9. उक्त कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिये जायेंगे और विलम्ब यह अन्य कारणों से लागत में किसी प्रकार का पुनरीक्षण अनुमत्त नहीं होगा। स्वीकृत लागत में अनुमोदित संख्या से अधिक हैण्ड पम्प नहीं लगाये जायेंगे, जहाँ पूर्व में हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं वहाँ न लगाकर आवश्यकता के स्थान पर ही अधिष्ठापित किये जायेंगे।
10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति-आयोजनागत-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-91-हैण्डपम्पो का अधिष्ठापन (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
11. यह शासनादेश राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि०यो०/रा०यो०आ०/मु०स०/2008, दिनांक 24.03.2008 में उल्लिखित निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

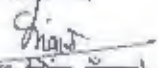
भवदीय,

(एम०एच० खान)  
सचिव

पृ०स० १८११ / उत्तीस(२) / ०८-(०१पे०) / २००८ तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी।
7. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री।
8. बजट अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. वित्त अनुभाग-२/वित्त बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ।
10. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(टीकम सिंह पुरी)  
संयुक्त सचिव